दिनांक : 23.07.2024 समय : 07.10PM

मुख्य समाचार

1- वित्त मंत्री ने संसद में किया बजट पेश, किसान, महिला, युवा और मध्यवर्ग के लिए दीं कई सौगात।
2- प्रधानमंत्री ने कहा- समाज के हर वर्ग को बजट से मिलेगी मदद. मुख्यमंत्री ने भी बताया ऐतिहासिक
3- राज्य मंत्रिपरिषद ने दी आईटी निवेश संवर्धन नीति में संशोधन को मंजूरी।
4- सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-यूजी परीक्षा दोबारा कराने का आदेश देने से किया इनकार।

बजट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमति सीतारामण ने बताया है कि विकसित भारत की दिशा में बजट में 9 प्राथमिकताएँ तय की गई हैं। ये है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और अगली पीढ़ी के सुधार। वित्तमंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए दो घोषणाएं कीं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं तीन लाख तक शून्य और तीन से सात लाख तक पांच प्रतिशत कर देय होगा। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

वित्तमंत्री ने बताया कि कृषि और सबंधित क्षेत्रों के लिए एक लाख 52 हजार करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख 66 हजार करोड रुपये के प्रावधान की घोषणा की है। अगले दो वर्ष में पूरे देश में एक करोड किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। दस हजार आवश्यकता आधारित संसाधन केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। बजट में इस बार सरकार ने सोने-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, चार्जर, कैंसर की तीन दवाएं और सोलर पैनल पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर्ड होने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक की राशि तीन किश्तों में दी जाएगी। इसके अलावा एक करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय-नीट

सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से आज इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस संबंध में दायर कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने का कोई प्रमाण नही है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थीं जिससे पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई।

न्यायालय ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने के गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा करने से 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा। आने वाले वर्षों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

पीएम- बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024-2025

विकसित भारत के लिए है जो चहुमुखी विकास सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है जिससे देश में करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय बजट पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। यह देश के लिए बेहतर विकास और उज्ज्वल भविष्य लेकर आया है।

बजट प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें महंगाई दर को कम करने की भावना परिलक्षित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित बजट प्रस्तुत किया गया है। डॉ. यादव ने कहा कि कृषि उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा बजट केन्द्रित है। उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने केंद्रीय बजट 2024-25 को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में विभिन्न वर्गों के कल्याण और देश के विकास की स्पष्ट झलक दिखती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कल्याणकारी बजट के लिए वित्तमंत्री को बधाई दी है।

उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट को निरानाजनक करार दिया है।

मंत्रि-परिषद बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए

म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। नई नीति से पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नव-गठित जिला निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किये जाने की स्वीकृति दी है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी मंजूरी दी गई।

मौसम

प्रदेश में मानसूनी स्ट्रांग सिस्टम की वजह से बारिश का दौर लगातार जारी है। अगले दो दिन भी प्रदेश में ऐसी ही बारिश जारी रहने के आसार है। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज पिछले कई दिनों बाद रिमझिम बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। उधर सिवनी में भारी बारिश हुई। मंडला जिले के थावर जलाशय के गेट खोले जाने से मंडला-सिवनी मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं नर्मदापुरम संभाग में हो रही तेज बारिश के कारण सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं।

मजदूर संघ

भारतीय मजदूर संघ अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजधानी भोपाल में इसके लिए देश भर से मजदूर नेता पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम से पहले ठेंगड़ी भवन (भारत माता चौराहा) से लेकर रवीन्द्र भवन तक एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। जिसके बाद उद्घाटन

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

संक्षिप्त समाचार

1- राज्य सरकार रक्षाबंधन से पहले अगले महीने की पहली तारीखे लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों के खाते में ढाई-ढाई सौ रुपये अतिरिक्त जमा करेगी।

2- नीमच जिले में राजस्व विभाग से संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष राजस्व सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 25 जुलाई को जिले की सभी तहसीलों के 16 ग्रामों में राजस्व अधिकारियों द्वारा विशेष राजस्व शिविर लगाए जाएगें।

3- खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत सेमलिया फाटे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई वहीं 20 लोग घायल हो गए। जबकि 8 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय खंडवा रेफर किया गया।

4- शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर के मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जाए।

5- एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नरसिंहपुर जिले में वृहद स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ग के लोग व स्वयंसेवी संगठन इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। खास कर नर्मदा तटों पर पौधरोपण किया जा रहा है।

6- भारतीय मजदूर संघ अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजधानी भोपाल में इसके लिए देश भर से मजदूर नेता पहुंच रहे हैं।